

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 522 / 2012 / हनुमानगढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स लूणाराम राजेन्द्र कुमार, संगरिया.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 523 / 2012 / हनुमानगढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेश कुमार राजेन्द्र कुमार, हनुमानगढ़ जं०.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21 / 06 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 250 व 252 / आरएसटी / श्रीगंगानगर / 10-11 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 23.6.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2000-01 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29, 65, 58 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों के तथ्य समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर विभाग को यह शिकायत प्राप्त हुई कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में माल के भौतिक हस्तान्तरण के बिना बोगस फर्मों से बोगस बिलों का लेन-देन किया जा रहा है और इन बोगस बिलों से करदत्त माल के पेटे अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद



१२-

लगातार.....2

किये गये कर योग्य माल के विरुद्ध समायोजन लिया जाता है। माल के पेटे दिखाया गया भुगतान बैंक में कॅश जमा करवाकर विक्रेता व्यवहारी को चैक जारी किया जाता है, तत्पश्चात् विक्रेता व्यवहारी के सेल्फ के चैकों से यह राशि उसी दिन नगद रूप में वापिस निकाल ली जाती है। इस प्रकार एक ही राशि को विभिन्न दिनांक में बार-बार जमा करवाकर विक्रेता व्यवहारी को एकाउण्ट पेई चैक दिये जाते हैं। बैंक खातों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि ये केवल वित्तीय लेन-देन है। बोगस बिल जारी करने वाली फर्में मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार, श्रीगंगानगर; मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर; मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया; मैसर्स बंधु ट्रेडर्स, संगरिया; मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया; मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स, संगरिया आदि एवं उक्त बिलों को लेने वाली प्रत्यर्थी फर्में मैसर्स राजेश कुमार राजेन्द्र कुमार हनुमानगढ़ व मैसर्स लूणाराम राजेन्द्र कुमार संगरिया तथा अन्य फर्में मैसर्स रौनक राम जगन्नाथ, संगरिया एवं अन्य फर्में शामिल हैं। उक्त व्यवसायियों का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि उक्त व्यवसायियों द्वारा आलौच्य अवधि में मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार श्रीगंगानगर; श्री शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया; मैसर्स बंधु ट्रेडर्स, संगरिया व मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर से क्रय संव्यवहार दर्शाये गये हैं।

4. इस प्रकार यह पाये जाने पर कि उक्त व्यवसायियों द्वारा वास्तविक रूप से माल की खरीद अपंजीकृत व्यवसायियों से की गयी है, किन्तु करापवंचन की नियत से माल को करदत्त बताने के लिये बोगस फर्मों से माल के बिल प्राप्त कर पंजीकृत व्यवसायियों से माल का क्रय करना बताकर कर योग्य माल कर चुकाकर बताये जाने का प्रयास किया गया है। उक्त जांच के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा ऐसा साबित करने पर कि व्यवसायी द्वारा क्रय संव्यवहार भौतिक रूप से नहीं किये गये, अपितु केवल बिल प्राप्त कर उनके भुगतान का लेखा जोखा बैंकों में दर्शाकर करापवंचन करने का प्रयास किया है व्यवसायी के विरुद्ध अभियोग बनाकर करापवंचित विक्रय पर कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण कर दिनांक 30.06.2003 को आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2006 को पुनः जांच एवं सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः दिनांक 29.01.2010 को आदेश पारित किये जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारियों की समस्त खरीद के संव्यवहारों को अविधिक एवं बोगस मानते हुए माल कर चुका (Tax Paid)



2/10

लगातार.....3

नहीं मानकर उस पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। पुनः पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.01.2010 के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलें इस विधिक आधार पर स्वीकार की कि दिनांक 30.11.2006 को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर जांच हेतु जो निर्देश दिये थे उसकी पालना नहीं की गयी एवं इसी तरह के समान तथ्यों पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों में क्रेता व्यवहारी का कर दायित्व नहीं माना गया है। अपीलीय आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

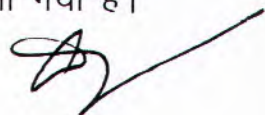
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

6. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलीय आदेश को अपास्त करने एवं राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए इन्हीं तथ्यों एवं उन्हीं तथाकथित बोगस संब्यवहार करने वाली फर्मा से खरीद किये गये माल पर कर दायित्व नहीं होने का निर्णय मैसर्स सरावगी रोलर फ्लोर मिल्स (प्रा0) लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2004) 9 टैक्स अपडेट 41 एवं उस निर्णय की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिविजन नं0 481/2004 निर्णय दिनांक 13.7.2005 न्यायिक दृष्टान्त (2005) 13 टैक्स अपडेट 134 में की जाने का कथन कर अपीलीय आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से कवर्ड होना बताते हुए राजस्व की अपील खारिज योग्य बताई।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

9. राजस्व द्वारा उक्त प्रकरणों में करापवंचन सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर अभियोग स्थापित किये गये हैं, जिनमें कुछ पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा उक्त प्रत्यर्थी व्यवहारियों को जारी बिल बोगस मानते हुए यह अवधारित किया गया कि इन व्यवसायियों ने करवंचना के उद्देश्य से पंजीकृत व्यवसायियों से भौतिक रूप से माल की खरीद ही नहीं की है बल्कि केवल करवंचना के उद्देश्य से, कर योग्य माल को करदत्त (S.T. Paid) बताने के लिये बिल ही प्राप्त किये गये हैं एवं बैंकों के जरिये लेन-देन भी केवल इन संब्यवहारों की पुष्टि हेतु ही किये गये हैं जबकि उसमें नगद रकम को जमा कराकर चैक देकर पुनः नगद राशि प्राप्त कर ली गयी है।



10. प्रत्यर्थी की ओर से विभाग द्वारा ही तत्समय समान तथ्यों पर अन्य फर्मों के विरुद्ध बनाये गये अभियोग में पारित आदेश को कर बोर्ड द्वारा अपास्त करने का दृष्टान्त पेश किया गया है उसका अध्ययन करने पर पाया कि उस प्रकरण में भी इन्हीं संदिग्ध विक्रेता फर्मों मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार, श्रीगंगानगर; मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी, संगरिया के बिलों को अस्वीकार कर, कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गयी थी, उन आदेशों को कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स सरावगी रोलर फ्लोर मिल्स (प्रा0) लिमिटेड, श्रीगंगानगर निणय दिनांक 26.4.2004 (2004) 9 टैक्स अपडेट 40 में खारिज किया गया है, एकलपीठ के निर्णय के पैरा संख्या 11, 12 व 13 निम्न प्रकार है :-

“11. मैने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रेकार्ड का अध्ययन किया। तीनों ही वर्षों में विवादित आदेशों से विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने प्रमुख रूप से यह माना है कि व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवसायियों से गेहूं की खरीद की गई है जबकि लेखापुस्तकों तथा उपलब्ध बिलादि से यह प्रतीत होता है कि माल पंजीकृत व्यवसायियों से क्रय किया गया है। वर्ष 1998-99 में मैसर्स लालचन्द राय हरीश कुमार तथा नारायण ट्रेडिंग कम्पनी से गेहूं की खरीद की गई है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मैसर्स लालचन्द राय हरीश कुमार दिनांक 21.01.2001 तक पंजीबद्ध था तथा उसका पंजीयन दिनांक 22.01.2001 को निरस्त किया गया है हालांकि यह निरस्तीकरण पूर्व तिथि से किया गया है पर इससे क्रेता को दिनांक 22.01.2001 से पूर्व यह जानकारी मिलना संभव ही नहीं था कि विक्रेता फर्म का पंजीयन माल खरीद के दिन निरस्त हो चुका है एवं प्रचलित पंजीयन प्रमाण-पत्र पर अविश्वास करना विभाग की अवमानना भी होती जिसे कि सरकार का कोई भी विभाग सहन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन दिनांक 31.03.2002 से निरस्त किया गया है। इससे यह साबित होता है कि वर्ष 1998-1999 में जब क्रेता-व्यवसायी ने इन फर्मों से माल खरीदा था तब वे बिक्री कर विभाग में पंजीबद्ध थे। वर्ष 1999-2000 में क्रेता व्यवसायी ने मैसर्स लालचन्द राय हरीश कुमार तथा मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार से माल खरीदा है। मैसर्स लालचन्द राय हरीश कुमार का पंजीकरण चूंकि दिनांक 22.01.2001 को निरस्त किया गया है अतः विवादित वर्ष में उसका पंजीयन प्रमाणपत्र प्रभावी ही था। इसी प्रकार मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार का पंजीयन दिनांक 27.03.2002 को पूर्व तिथि से निरस्त किया गया है पर क्रेता के लिए विवादित समयावधि में इसका पंजीयन प्रमाण-पत्र माल खरीदने हेतु नियमानुसार प्रभावी था। इसी प्रकार वर्ष

लगातार.....5

2000-01 में क्रेता व्यवसायी ने मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार तथा मैसर्स मोहित ट्रेडिंग कम्पनी से माल खरीदा है। यहां तथ्य यह है कि बजरंग राय विनोद कुमार का पंजीयन दिनांक 27.03.2002 को समाप्त किया गया है तथा मोहित ट्रेडिंग कम्पनी के संबंध में उसका पंजीयन क्रमांक 1316/03612 को निरस्त करने का सन्दर्भ रेकार्ड में उपलब्ध होना जान नहीं पड़ता है। इससे भी यही साबित होता है कि इस विवादित वर्ष में भी क्रेता ने पंजीकृत व्यवसायियों से माल खरीदा है। पंजीयन प्रमाण-पत्र पूर्व तिथि से समाप्त कर देने से उसका उल्टा प्रभाव क्रेता पर नहीं पड़ सकता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (1998) 109 एसटीसी 439 में यही माना है कि क्रेता व्यवसायी द्वारा कानूनन विक्रेता के पंजीयन प्रमाण-पत्र पर यकीन कर व्यवसाय करना वैध है। अतः मैं इस न्यायिक दृष्टांत के अनुरूप एवं व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से सहमति रखता हूँ कि क्रेता ने तीनों वर्षों में पंजीकृत व्यवसायियों से माल क्रय किया है।

12. जहां तक बैंक खातों की जांच के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी की राय है तो वे यह साबित नहीं कर सकते हैं कि ये खाते बोगस या फर्जी थे। ये खाते सही व्यक्तियों/फर्मों के नाम से थे तो उसमें से राशि भी यही व्यक्ति ही निकाल सकता था। यह संभव ही नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति इन खातों में राशि जमा करा कर फिर निकाल ले। राशि निकालने के लिए वही अधिकृत होता है जो कि खाते को आपरेट करता है, बिना उसकी सहमति के राशि निकालना संभव ही नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में व्यवसायियों के खाते अस्तित्व में थे तथा उन्हीं के द्वारा जारी किये गये 'सैल्फ' के चैक्स से रकम निकाली गयी है। खाताधारक अपनी रकम को कब निकाले तथा इसके लिए वह किसको अधिकृत करे यह उसका दृष्टिकोण है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी अपनी मान्यता उन खाताधारकों पर थोप नहीं सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि खातों में राशि जमा करना तथा निकालना तकनीकी एवं विधिक रूप से बिल्कुल सही है। कर निर्धारण अधिकारी बैंक से राशि जमा कराने को भुगतान क्यों नहीं मानते है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि विक्रेता किस प्रकार से फर्जी थे तथा जब उन्होंने माल बेचा है तो विक्रय कर उनसे क्यों वसूल नहीं किया जाए।

13. मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी तथा मैसर्स बजरंग राय विनोद कुमार के व्यवसाय स्थल पर कार्यरत नहीं होने का प्रश्न है तो इससे उनके द्वारा विक्रय किया गया माल फर्जी बिक्री या खरीद की श्रेणी में कैसे आयेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीकरण दिनांक 31.03.2002 से



202

लगातार.....6

निरस्त किया है तथा दिनांक 26.02.2002 की रिपोर्ट में यह अंकित है कि मालिक व मुनीम व्यवसाय स्थल पर नहीं मिले है तो इस दिनांक से तीन वर्ष पूर्व अर्थात् वर्ष 1998-99 में किये गये संव्यवहार को फर्जी कैसे माना गया है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है, किस आधार पर यह माना गया कि वर्ष 1998-99 में विक्रेता घोषित व्यवसाय स्थल पर कार्यरत नहीं था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत जांच भी नहीं की है। पड़ोसियों ने यदि यह बतलाया था कि यह फर्म फर्जी बिल बनाती है तो उसकी विस्तृत जांच कर, कर दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये था तथा क्रेता के पास उपलब्ध बिल को असत्य साबित करना चाहिये था जबकि उसके अनुसार उसने भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया था। इसी प्रकार मैसर्स बजरंगलाल विनोद कुमार ने तो कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 27.03.2003 के अनुसार 1999-2000 में रुपये 2,54,41,941/- का संव्यवहार किया था तथा पांच एस.टी. 17 भी प्राप्त किये थे। जब तक निर्धारण अधिकारी स्वयं इन संव्यवहारों को मानते हैं तो क्रेता-व्यवसायी की खरीद को इससे जोड़कर देखना उचित होगा और यदि विक्रेता जो कि पंजीबद्ध था ने कोई फर्जी काम किया था तो उसके लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये थी तथा उसके अपराध के लिए क्रेता पर कर दायित्व निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।”

11. उक्त निर्णय के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरणों में हूबहू हैं एवं कर बोर्ड के उक्त आदेश अनुसार द्वितीय विक्रेता पर करारोपण अविधिक माना गया है एवं प्रथम पंजीकृत व्यवसायी पर ही करदायित्व माना है। कर बोर्ड के उक्त आदेश की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल रिविजन संख्या 481/2004 व अन्य सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सरावगी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा० लि० के निर्णय दिनांक 13.07.2005 न्यायिक दृष्टान्त 13 टैक्स अपडेट 134 में की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"The learned Tax Board has found that material on record establishes that the registration of the seller has been subsisting upto 21.01.2001, and was subsequently cancelled with retrospective effect. Likewise, the registration of one of the seller was cancelled on 31.03.2002, While that of the other two dealers was cancelled on 27.03.2002, and therefore, in view of the judgment of Hon'ble the Supreme Court in **State of Maharashtra vs. Suresh Trading Co. (1998) 109 STC 439**, it is lawful for the purchaser to enter into transaction relying on the validity of the registration. Regarding

लगातार.....7




200

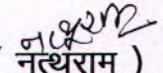
withdrawal of the amounts from the bank, it was found to be valid act on the part of the account holders. Similarly, it was found that the assessee had purchased goods from M/s. Bajranglal Vinod Kumar against declaraitons ST-17, and therefore, if any action was required to be taken, it was required to be taken against the sellers, regarding registration of the vehicles, it was found that the registering authority had certified the existence of registration of the concerned vehicles. Then, bonafied endorsements of Krishi Upaj Mandi Samiti were also found on the certain bills. Interalia, on this basis it was found that it cannot be said that the assessee had purchased the goods from the unregistered dealer."

12. हस्तगत प्रकरण के तथ्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णयों के तथ्यों से पूर्णतया समान हैं तथा विक्रय संब्यवहार भी उन्हीं विक्रेताओं के थो जो इन प्रकरणों में विवादित हैं। इन प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपास्त किया गया है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना अविधिक है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं एवं अपीलीय आदेश दिनांक 23.06.2011 की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।


(क. एल. जैन)
सदस्य


(नत्थूराम)
सदस्य